

(c) The Central Council for Research in Indigenous System of Medicine and Homoeopathy has decided that the proposed Institute be located in Calcutta. An allocation of Rs. 14,65,000/- for spending during the Fourth Plan period for this Institute has been made.

**Payment of Interim Relief to Central Government Employees without any reference to Third Pay Commission**

\*1245. SHRI S. M. BANERJEE :  
SHRI D. AMAT :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government Employees' Organisations have demanded payment of interim relief without any reference to the proposed third pay Commission ;

(b) whether this demand has been made because of wage rise in other public sector projects ; and

(c) if so, the reaction of the Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b). Yes Sir.

(c) The Pay scales of employees of Public Sector Undertakings are fixed under different conditions and with reference to different considerations which do not apply to Government employees. The question of interim relief, if any, as also the date of its effect are already included in the terms of reference of the new Pay Commission.

**चौथी पंचवर्षीय योजना में कमी वाले राज्यों को विशेष सहायता**

\*1246. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कमी वाले राज्यों के लिये विशेष सहायता की जो व्यवस्था की गई है, गुजरात

तथा महाराष्ट्र सरकार ने उसका विरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने किन तर्कों तथा कारणों पर इस व्यवस्था का विरोध किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री २० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने यह विचार प्रकट किया है कि योजना आयोग ने साधनों की कमी वाले कुछ राज्यों को चयनात्मक आधार पर जो विशेष सहायता देने की सिफारिश की है, वह सहायता सभी राज्यों में समान आधार पर बाँटी जानी चाहिये ।

ऋणों के रूप में विशेष सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जायेगी जिन के साधन आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, अनिवार्यतः कम होंगे । इसलिये, ऐसे राज्य जिन के साधनों में इस प्रकार की कमी होने की संभावना न हो, विशेष सहायता के पात्र न होंगे और इस प्रकार की सहायता को समान आधार पर बाँटे जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**Manufacture of Barrels by Standard Drum and Barrel Manufacturing Company and Hind Galvanising and Engineering Company for Indian Oil Corporation**

\*1247. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 40 on the 23rd February, 1970 and state :

(a) why unusual delay is being caused in fixing responsibilities on the concerned officers of the Indian Oil Corporation for their lapses for not including clearly